जीआईएस-2025 : राजधानी में होगा वैश्विक निवेशकों का महासंगम

भोपाल(काप्र)।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 को लेकर तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं और विशिष्ट मेहमानों की सूची भी लगभग फाइनल हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूद अपार संभावनाओं से परिचित कराने के लिए करीब 60 देशों से उद्यमियों को आमंत्रित किया है। इसमें 13 राजदूतों, 6 उच्चायुक्तों और प्रमुख रणनीतिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई महावाणिज्यदूतों की भागीदारी भी सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव की अनूठी पहल देश के महानगरों में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग और यूके, जर्मनी और जापान में निवेशकों को आकर्षित करने रोड-शो के आयोजन ने न सिर्फ क्षेत्रीय उद्योगों को एक सुदृढ़ प्लेटफार्म दिया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राजनयिक कोर की भागीदारी का नेतृत्व

जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड और मलेशिया के महावाणिज्यदूतों सहित मिशनों के प्रमुखों द्वारा किया जा रहा है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, नीदरलैंड और कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राजनयिक उपस्थिति को और प्रभावी करते हुए, नेपाल, मोरक्को, जिम्बाब्वे, अंगोला और बुर्किनाफांसो के राजदूतों के साथ रवांडा, सेशेल्स, जमैका, लेसोथो और युगांडा के उच्चायुक्तों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।

जीआईएस में विश्व बैंक की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीआईएस में विश्व बैंक का नेतृत्व कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे कर रहे हैं। उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल परिवर्तन के वरिष्ठ विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त निवेश संवर्धन एजेंसियों के संगठन (डब्ल्यूएआईपीए) का प्रतिनिधित्व उप कार्यकारी निदेशक दुष्यंत ठाकोर करेंगे। जीआईएस भोपाल में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसियों ने भी अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इनमें महानिदेशक हिरोयुकी कितामुरा के नेतृत्व में जेट्रो (जापान), निदेशक सुश्री सीमा भारद्वाज के प्रतिनिधित्व में जर्मन ट्रेड एंड इन्वेस्ट और इन्वेस्ट ओटावा का वरिष्ठ नेतृत्व शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में इतालवी व्यापार एजेंसी, कनाडा की व्यापार आयुक्त सेवाएं, ऑस्ट्रेड (ऑस्ट्रेलिया) और मैट्रेड (मलेशिया) का भी प्रमुख प्रतिनिधित्व है, जो मध्यप्रदेश में मजबूत क्रॉस-महाद्वीपीय निवेश रुचि को दर्शाता है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 को द्विपक्षीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से भरपूर समर्थन मिला है, जो प्रमुख आर्थिक साझेदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रबंध निदेशक श्री स्टीफन हालुसा के

नेतृत्व में इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईजीसीसी) और जर्मन इंडियन इनोवेशन कॉरिडोर (जीआईआईसी) भारत-जर्मन आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता लेकर आए हैं। सिंगापुर के आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व सिंगापुर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसआईसीसीआई) द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी हैं, जो प्रौद्योगिकी और निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

जीआईएस की विविध द्विपक्षीय भागीदारी में चेयरमैन रमेश अय्यर के नेतृत्व में कोरिया में भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसीके), अध्यक्ष जेजे सिंह के प्रतिनिधित्व वाले इंडो-पोलिश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईपीसीसीआई) और इंडिया जिबूती चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईडीसीसी) शामिल हैं। ये चैंबर सीमा पार निवेश को सुविधाजनक बनाने और मध्यप्रदेश और उनके संबंधित क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को सशक्त बनाने में बहुमूल्य विशेषज्ञता लेकर आए हैं।

जीआईएस में शामिल होने वाले रूस के उल्यानोवस्क क्षेत्र के गवर्नर रुस्किख अलेक्सई युरेविच रूस के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और व्यापारिक नेतृत्व शामिल हैं। साथ ही, जिम्बाब्वे के उद्योग और वाणिज्य उप मंत्री राज मोदी अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो मध्यप्रदेश और अफ्रीका के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग का संकेत है। कई अन्य मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आने की शीघ्र ही पुष्टि करेंगे।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 रणनीतिक रूप से प्रमुख निवेश स्रोत देशों को भागीदार देशों के रूप में शामिल करता है, जो मध्यप्रदेश की केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय पहुंच पर आधारित है। जर्मनी 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक प्रमुख भागीदार के रूप में साथ आ रहा है। इसमें एसएपी, केपीएमजी और महत्वपूर्ण उद्यम पूंजी फर्मों के उद्योगों के नेता शामिल हैं। जापान की साझेदारी, जेट्रो की व्यापक भागीदारी और प्रमुख क्षेत्रों में संभावित निवेश शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए राज्य के रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। यूनाइटेड किंगडम की साझेदारी नवाचार और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता लाती है, जबकि कनाडा के साथ चल रही चर्चाएँ पारस्परिक आर्थिक हित के क्षेत्रों में आशाजनक विकास का मार्ग दिखाती हैं। इन साझेदारियों को निरंतर द्विपक्षीय जुड़ाव और प्रदर्शित निवेश प्रतिबद्धताओं से सावधानीपूर्वक विकसित किया गया है, जिसने मध्यप्रदेश को वैश्विक उद्योग के नेताओं के लिए एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली के होटल इम्पीरियल में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आज अंतरित करेंगे लैपटॉप की राशि

89,700 विद्यार्थियों के खाते में सीधे पहुँचेगी 224 करोड़ रूपए की राशि

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 21 फरवरी को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खाते में लैपटॉप की राशि अंतरित करेंगे।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम प्रात: 10:30 बजे राजधानी के आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में होगा। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। डॉ. यादव मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा वर्ष 2023-24 में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले 89 हजार 710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सिंगल क्लिक से उनके बैंक खातों में 224 करोड़ रूपये की राशि भी अंतरित करेंगे। ये विद्यार्थी वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को 25 हजार रुपये की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिये दी जा रही है। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर और सांसद आलोक शर्मा भी उपस्थित रहेंगे।

मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्यों के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। डॉ. यादव ने कामना की है कि प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध मिजोरम राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करे। उन्होंने अनूठी संस्कृति और जीवन शैली से सभी का हृदय जीतने वाले मिजोरम के नागरिकों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी है।

जैविक खेती पर कार्यशाला का शुभारंभ आज

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को प्रात: 10:30 बजे राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र बरखेड़ी कलां में जैविक खेती पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना भी उपस्थित रहेंगे।

वर्तमान खेती में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि एवं वातावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण, मृदा उर्वरता तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण और उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कृषि में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिये जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में जैविक कपास, फल एवं सब्जियां एवं अन्य फसलों के लिए के लिए जैविक खेती पद्धति एवं उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए रणनीति तैयार की जायेगी। कार्यशाला में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एफपीओ एवं जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदेश में 11 एग्रो क्लाईमेटिक जोन में विभिन्न फसलों की व्यापक क्षेत्र में खेती की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, स्वस्थ खाद्य उत्पाद एवं बाजार मांग के दृष्टिकोण से व्यापक क्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक खेती की संभावनाएं हैं। प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर व्यवहारिक कार्ययोजना, नीति तैयार करने, कॉमन संस्थात्मक प्लेटफार्म विकसित करने और प्रदेश में प्राकृतिक एवं जैविक परिदृश्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिये उपयोगी होगी।

अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक बढ़ाई

प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था में रिक्त पदों के विरूद्ध सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली गई हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस शैक्षणिक वर्ष में विद्यालय में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिये अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी हैं। इस संबंध में संचालनालय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकूल प्राचार्य और शाला प्रभारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत बनाना है: चौधरी

मप्र कांग्रेस कार्यालय में प्रथम आगमन पर नवनियुक्त प्रभारी का भव्य स्वागत

भोपाल (काप्र)।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गुरुवार को नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के राजधानी आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूल-मालाओं और जयघोष के साथ उनका अभिनंदन किया।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। बैठक में प्रदेश संगठन को मजबूत करने, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक बदलाव और पार्टी की रणनीति को लेकर व्यापक चर्चा की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी को मजबूती देने और जनहित के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के संकल्प को दोहराया। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने के लिए सभी को संगठित होकर काम करना होगा। उन्होंने पार्टी की एकता और मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि हम सबको मिलकर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाना है और जनहित के मुद्दों को प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से उठाना है, जनता के हितों के लिए सड़क से सदन तक पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना है। आगामी कार्ययोजना बनाकर जल्द ही प्रदेश भर में भ्रमण कर पार्टी की मजबूती के लिए एक-एक कार्यकर्ता से मुलाकात कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की जायेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश और संकल्प प्रदेश में एक नया बदलाव लाएगा। उन्होंने सभी से एकजुट होकर कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और सशक्त संगठन निर्माण की दिशा में कार्य करने की अपील की। बैठक को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी संबोधित किया। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों, जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों और अन्य कार्यक्रमों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में हर स्तर पर मजबूती से संघर्ष करेगी और

जनता की आवाज को बुलंद करेगी। बैठक के दौरान संविधान की उद्देशिका का वाचन कर उपस्थितजनों के लिए संविधान की रक्षा की शपथ दिलायी गई। बैठक के बाद श्री चौधरी और श्री पटवारी ने विधायकगणों, जिला/ शहर कांग्रेस अध्यक्षों, मोर्चा संगठनों, विभाग और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ पृथक से संगठनात्मक चर्चा की।

फिटजी के चेयरमैन से पूछताछ के बाद ही वापस भोपाल लौटेगी पुलिस टीम

भोपाल(काप्र)।

राजधानी मे छात्रों से करोड़ों रुपए की फीस जमा कराने के बाद कोचिंग बंद करने गायब होने वाले फिटजी के चेयरमैन डीके गोयल से पूछताछ करने के लिये भोपाल पुलिस पार्टी दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में स्थित कोचिंग के मुख्य ऑफिस में दबिश देकर टीम ने भोपाल में संचालित कोचिंग से संबंधित कई अहम दस्तावेज जप्त किए हैं। इन दस्तावेजों से पता चलेगा कि भोपाल में छात्रों से कितनी फीस वसूली गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चेयरमैन डीके गोयल के बारे में दिल्ली के स्टाफ ने पुलिस टीम को उसके बाहर जाने की जानकारी दी है। पुलिस टीम को उससे पूछताछ करके ही लौटने के निर्देश देते हुए चेयरमैन के वापस आने तक वहीं पर रुकने को कहा गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भोपाल सेंटर के जो अकाउंट सामने आए हैं। उनमें ज्यादा रकम नहीं मिली है। दिल्ली से जो रिकॉर्ड जब्त किया है, उससे पता चलेगा कि भोपाल के छात्रों से ली गई फीस किन-किन खातों में गई। ऐसे खातों को फ्रीज कराने की कार्रवाई की जाएगी।

स्पेशल खबर *प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के...*

लाईफ विजन के अनुरूप है मध्य प्रदेश की बॉयो फ्यूल योजना: डॉ. यादव

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बॉयो फ्यूल बॉयो फ्यूल योजना-2025 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (एलआइएफई) अभियान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन पर जोर दिया गया है।

यह योजना प्रदेश की कृषि शक्ति का पूर्ण लाभ उठाते हुए नवाचार को बढ़ावा देगी। प्रदेशवासियों के लिए हरित और समृद्ध भविष्य के साथ, योजना से प्रदेश में बॉयो फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बॉयो ऊर्जा संयंत्र, फीड स्टॉक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर व्यापक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। योजना से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉयो फ्यूल योजना-2025 राज्य की आर्थिक समृद्धि, हरित ऊर्जा उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए क्रांतिकारी पहल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सतत विकास और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। उनकी प्रेरणा से मध्यप्रदेश सरकार भी ऐसी योजनाएं बना रही है, जो दीर्घकालिक रूप से पर्यावरण के अनुकूल हों और रोजगार सृजन को बढ़ावा दें। इस योजना से प्रदेश में कृषि एवं जैव अपशिष्ट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा और राज्य हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। नवकरणीय ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बॉयो फ्यूल योजना-2025 को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।

प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत बॉयो फ्यूल उत्पादन संयंत्र स्थापना के लिये भूमि आवंटन, निवेश प्रोत्साहन, आधारभूत संरचना विकास में सहायता

और कर रियायतें प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को अतिरिक्त आय के साधन मिलेंगे और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बॉयो फ्यूल यूनिट्स के लिए बुनियादी निवेश प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर अनुदान और विद्युत शुल्क में छूट जैसी अनेक सहूलियतें दी जा रही हैं, जिससे प्रदेश को जैव ईंधन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण अनुकूल उद्योगों के विकास को गति मिलेगी।

डॉ. यादव ने कहा कि 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बॉयो फ्यूल योजना को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। समिट में देश-विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के दिग्गज और नीति-निर्माता भाग लेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से बॉयो फ्यूल और ग्रीन एनर्जी में निवेश को आकर्षित किया जाएगा।

सप्लाई चैन का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉयो फ्यूल योजना में मुख्यत: बॉयो सीएनजी, बॉयो मास ब्रिकेट एवं पेलेट और बॉयोडीजल जैसे ईंधन शामिल हैं। यह बॉयो फ्यूल उत्पादन के सभी पहलुओं को कवर करती है, जिसमें फीडस्टॉक खेती, उत्पादन तकनीक, वितरण और उपयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। बॉयो फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एवं बॉयो ऊर्जा संयंत्रों को कई लाभ प्रदान किए जाएंगे, साथ ही किसान संस्थाओं को कृषि उपकरण हेतु सब्सिडी, बॉयो मास एवं खाद की बिक्री सुनिश्चित करने और सप्लाई चैन विकसित करने के प्रावधान भी शामिल हैं। बॉयो फ्यूल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बॉयो मास उत्पादन के लिए सरकारी भूमि का उपयोग कलेक्टर दर के 10 प्रतिशत वार्षिक शुल्क पर प्रदान किया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि योजना के तहत बॉयो फ्यूल यूनिट को 200 करोड़ रूपये तक का बुनियादी निवेश प्रोत्साहन (बीआईपीए) उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही बिजली, पानी, गैस पाइप लाइन, सड़क, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (ईटीपी, एसटीपी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण) के विकास हेतु 50 प्रतिशत प्रोत्साहन (अधिकतम 5 करोड़ रूपये तक की सहायता) प्रदान की जाएगी। विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर में 10 साल तक की छूट दी जाएगी और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 500 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश पर अनुकूलित पैकेज भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, आईपीआर एवं क्वालिटी कंट्रोल सहायता का प्रोत्साहन भी योजना में शामिल है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com